फेस्टिव सीजन में बढ़ते दाम को रोकने के उपाय में जुटी सरकार

शुगर इंडस्ट्री को इंपोर्ट के प्रस्ताव पर सख्त ऐतराज

[जयश्री भोसले | पुणे]

इंपोर्ट की इजाजत को लेकर अटकलों से शुगर इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई है। उसका कहना है कि अगर सरकार इंपोर्ट की अनुमति देती है, तो इससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। इस बात को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगामी फेस्टिव सीजन के दौरान शुगर की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार इसके इंपोर्ट की इजाजत दे सकती है।

जुलाई में इन्फ्लेशन दो साल के हाई लेवल यानी 6.07 फीसदी पर रही। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार शुगर की कीमतों पर नजर रख रही है। फूड मिनिस्टर राम विलास पासवान ने पिछले हफ्ते फिर से शुगर मिल मालिकों से इसकी कीमतों को स्टेबल रखने का अनुरोध किया।

इंडस्ट्री सूत्रों ने बताया कि सरकार शुगर की मिल स्तर की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से नीचे रखना चाहती है। इस इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'अगर शुगर मिलों के स्तर पर कीमतों 40 रुपये किलो से ऊपर जाती है, तो सरकार शुगर इंपोर्ट की इजाजत दे सकती है।' सूत्रों की मानें तो शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसटीएआई) के एक कार्यक्रम में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि इंडस्ट्री को कच्ची चीनी के इंपोर्ट की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

हालांकि, शुगर इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से का मानना है कि देश को शुगर इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अध्यक्ष तरुण साहनी ने बताया, 'अगर शुगर का इंपोर्ट होता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा और पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी की शुगर इंडस्ट्री और राज्य के किसानों के लिए यह बेहद नुकसानदेह होगा। 2016 में मॉनसून सीजन बेहतर रहने से गन्ने की बुआई तेज हो गई है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 2017-18 में गन्ने की बंपर फसल की उम्मीद और यह इसकी खपत से भी ज्यादा हो सकती है।' बहरहाल, शुगर इंडस्ट्री चिंतित है। शुगर की कीमतें भले ही एक साल से भी कम में महाराष्ट्र की मिलों में 20 रुपये किलो से बढ़कर 33 रुपये किलो तक पहुंच गई हों, लेकिन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें काफी लोन चुकाना है।

रिगा शुगर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ओ पी धानुका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है, 'इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बिजनेस में शामिल कुछ इच्छुक पार्टियां अब शुगर के इंपोर्ट में भी दिलचस्पी दिखा रही हैं...भारत को न तो शुगर का इंपोर्ट करना चाहिए और न ही एक्सपोर्ट। एडवांस लाइसेंस स्कीम के तहत जो भी शुगर इंपोर्ट हुआ है, उसे देश से बाहर भेजा जाना चाहिए।' इंडस्ट्री का आरोप है कि सरकार सब्जियों और बाकी फूड आइटम्स पर इन्फ्लेशन को काबू में नहीं रख सकती है, इसलिए शुगर पर फोकस कर रही है।

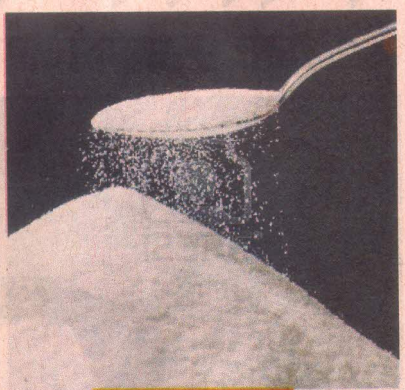

अगर शुगर का इंपोर्ट होता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा और पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी की शुगर इंडस्ट्री और राज्य के किसानों के लिए यह बेहद नुकसानदेह होगा

तरुण साहनी
अध्यक्ष, इस्मा